



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रारंभिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

मई विल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1981/ज्येष्ठ 8, 1903

No. 117]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1981/JYAIKISTHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असाधारण संकलन के
लिए रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-28 आईटीसी(पीएन)/81

मई विल्ली, 29 मई, 1981

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय:—1980-81 के लिए येत 2.46 विलियन (अरण सहायता) की जापान अनुदान सहायता से सम्बन्धित लाइसेंस दाताएँ।

मिसिल संख्या—आईटीसी/23(14)/80-81—जापान अनुदान सहायता येत 2.46 विलियन (अरण सहायता) के अन्तर्गत निम्नी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में आयातकर्ताओं के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली ऐसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिणाम-1 और 2 में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिक सूचित की जाती हैं।

कु. रौमा: मनुमेश, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण

परिशिष्ट-1

जापान की सरकार द्वारा प्रवान किए गए 1980-81 के लिए 2.46 विलियन (येत 2,463,559,000/-) (अरण सहायता) के जापानी अनुदान सहायता के प्रत्यार्थी द्वारा आयातकर्ता के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस दाताएँ।

खण्ड-1-सामान्य शर्तें :

(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.46 विलियन जापानी अनुदान सहायता ओर ५० मी० और विकासशील वेशों के लिए में संगठित की गई है। तबनुसार, इस अरण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पर्याप्त वस्तुएँ और उनसे सम्बन्धित प्रारंभिक सेवाएँ जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्दृत सभी वेशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस अरण के अन्तर्गत पात्र स्वातंत्र्य देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र भवें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है।

(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक “1980-81 के लिए 2.46 विलियन जापानी अनुदान सहायता होगा”। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत “एस/जे०एन” होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण के आयात लाइसेंस के अधिकारी पर में भी द्वितीय जाएंगे।

(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अनियन्त्रित विवेशी मूद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुसन्धान आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकारी के कामीशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकारी को भारतीय रूपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इन्हें लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस दाताएँ को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से

गम्पक करना चाहिए जो इग मामले में आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीम-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की नियम से) 4 महीनों की अवधि के भीतर) अधर संचित (टीए) आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन काय आदेशों या काय संविधानों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्थित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिनवताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिनवताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकारणीय नहीं है।

(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेके की इस शर्त का लक्ष्य अनुपालन किया गया नहीं गमका जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की नियम से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश की नहीं दिए जा सके हन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा फालता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अधिक के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की नियम रो 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरावाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पालना के आधार पर विचार करेंगे और अन्य निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोलार्डान के लिए आविर्द्धी नियम निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नियम 31-3-1982 के बाद की न हो।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करने समय इयान में रखी जाने वाली विवेप बातें:— 2(1)(क) ठेके का मूल वेतन या य० एस० डालर या पीएड स्टारिंग में एक येत, एक सेन्ट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अधिकत होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिनवता का कमीशन, आदि कार्य हो से वश शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रपवे में चुकाना चाहिए। भारतीय रपवे या किसी अन्य सुना से ठेके का मूल्य किसी भी वर्तिति में अधिकत नहीं होना चाहिए। जहाज पर्वत नियुक्त लागत-बीमा और भाड़ा घनराशि अलग-अलग प्रवासित को जा सकती है परस्त ठेके में यथा स्पष्ट कर देने चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय घनराशि होगी।

(7) संविदा में नकद आधार पर अधिनि वैक शाफ इण्डी, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोलार्डान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(8) अब आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश के बाद अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के महे के बाद एक संभिता की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संभिता की प्रविष्टि की अनुमति या जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की नियम के भलाल बाद पूर्व अनुमोदन ले सेना चाहिए।

(3) संभरक की पात्रता:

संभरक पात्र स्वीकृत देशों का राष्ट्रिय होगा या पात्र संघ देशों में पंजीकृत और समाजिक व्यापिक अवक्त होगा।

खण्ड-3 संभरण ठेकों में निम्नलिखित गत विवेप रूप से समाजिक होनी चाहिए:—

3(1) 1980-81 के लिए 2.46 लिलिपन के अनुवान सहायता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18 मार्च, 1981 को भारत और जापान की मरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार को गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्रधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1980-81 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन वैक शाफ इण्डी, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग, य० सी० ओ० बैक स्टारिंग, पार्सिपामेन्ट स्ट्रीट, नई विल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अनेकत हो।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में व्यवस्था हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पंतलवान की व्यवस्था करने की तैयार है और उसके लिए सम्बन्धित माल की सुरक्षिती के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियो की अधिसूचित करवाएगा जिसमें उल्लिखित व्यवस्था की जाए। विवेप मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचित की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक और देने हुए प्रत्येक पोलार्डान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4(1) ऐसे ही आदेशों को अनितम रूप दे दिए जाएं हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पाटियों द्वारा विश्वित हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र-पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए काय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा विश्वित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-3 के प्रस्तुत प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के अवैदेत" की 2 प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां भवर संवित (टीए) आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई विल्ली की भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आणोधनों से उत्तम सभी संविदा संशोधनों के निए भी लागू होंगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज, "ए/पी जारी करने के लिए प्रावेनपत्र" और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज मही पाएं जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, और भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के वैक और जापान अनुभाग, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्सिपामेन्ट स्ट्रीट, नई विल्ली-110001 वैक शाफ इण्डी, टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के वैक और जापान अनुभाग, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावाग, टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं देशा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलवान प्रभावी करने के बाद विवेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज मही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विवेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की अवस्था करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्च, भारत में आयातक के सम्बन्ध बैंक ग्राहा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए जाएंगे ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड 5—रुपया जमा करने का उत्तराधारियत

5(1) मूल विनियम पौत परिवहन दस्तावेज माथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बन्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीय कूट बैंक (जो अनुबन्ध-3 के-ए में उल्लिखित है) की शास्त्रा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट के बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विवेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू०एस० डालर/पोण्ड स्टार्टिंग धनराशि के बगवार रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विवेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से आमतौर पर रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिमाव लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं० 103 आईटीसी (पी०एन०)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। व्याज बोनों दिनों, अर्थात् जिम दिन विवेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आईटीसी (पी०एन०)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना स० 74-आईटी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू०एस० डालर/पोण्ड धनराशि के बगवार रुपाएं की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचना सं० 8 प्राई०टी०सी०० (पी०एन०)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिवर्तों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तराधारित सम्बद्ध, भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिम लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह “के डिपोजिटस एवं एडवान्सिंग 843 सिलिंडर हिपोजिटम—डिपोजिट्स फोर परचेजिंग एट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा परचेजिंग परचेस ग्रान्ट एड रुपया सहायता)।”

5(2) उल्लिखित धनराशि या सो भारतीय रिजर्व बैंक, नई विली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, विली में सरकार की साक्ष में भक्त जमा हाली चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक

आफ इण्डिया की किसी शास्त्रा या इसके उपर्युक्त किसी भी राष्ट्रीय कूट बैंक इण्डिया से प्राप्त एक हृणी (डिमार्ड ड्राइ) के माध्यम में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शास्त्रा, दिल्ली-6 (हृणी ग्राहक और प्राप्तक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पी०एन०)/68, दिनांक 30-8-68 सं० 233-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ये सांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी उपर निर्धारित तरीके गे वह अतिरिक्त धनराशि सेवा लेखों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विविध कालमों का भग्ने गमय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 103-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 12-10-76 के माध्यम पक्षी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन प्रेषण और प्रविकारी (यदि काई हो) के पूर्ण व्यौदे” में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खालान चालान में निम्नलिखित व्यौदे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके गम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के माध्यम लिए किए जाने हैं।

(ग) विवेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह चुकाए गया है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(आज की गणना विवेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में समन्वय संपाद्य जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए भी जानी है।)

उसके पश्चात् सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्रधिकार पत्र का संबंध देते हुए और बीजक नथा पौत परिवहन दस्तावेजों का संलग्न करते हुए खालान चालान रुपया जमा करने का माध्यम देते हुए पंजीकृत द्वारा सी०ए०ए०ए० ए० दिनांक 1 ओक्टोबर 1980 को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपाएं का निक्षेप बैंक आफ इण्डिया, टोकियो से अवायायों की सूचना और अपरिवर्तीय पौतलशान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तस्काल द्वारा सी०ए०ए०ए० ए०, वित्त मंत्रालय (अधिकारी कार्य विभाग), नई विली को सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इण्डिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित “ए०” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 6—विविध घटों :

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के लिए प्रधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पौतलशानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के मम्बन्ध में और जो पौतलादान होने वाली हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट

अमेरिका-उत्तरी और दक्षिण (क्रमसः)

वेस्ट हॉलीवूड (शास्त्रा) एन० आई० ई०

(क) मंबंधित राज्य (1)

(स) प्राप्तित राज्य (2)

4. विद्यार्थी अमरीका :

अर्जेन्टीना

बोलिविया

आजील

चिली

कोलम्बिया

फालकलैंड द्वीप समूह

फांसिसी गिर्मी

गुयाना

पाराग्वे

पीर

सूरिनाम

उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बहरीन

इजराइल

जोड़ेन

लेबनान

ओमन

सिरियाई अरब गणतंत्र

यूनाइटेड अरब अमिरात

यमन अरब गणतंत्र (3)

यमन जनवादी ई० आर० (4)

6. दक्षिण एशिया :

अफगानिस्तान

बांगला देश

भूटान

बर्मी

भारत

मालद्वीप

नेपाल

पाकिस्तान

श्रीलंका

7. मुद्रुर पूर्वी एशिया :

बुनेरै

हांगकांग

ख्मेर गणतंत्र

कोरिया गणतंत्र

लाओस

मकान्डो

मलेशिया

फिलिपीन

सिंगापुर

ताइवान

थाईलैंड

तिब्बत

वियतनाम गणतंत्र

वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओर्सनिया :

कोक द्वीप समूह

फिजी

गिल्खट और इलाइस द्वीप

फारिसी पोलिनेशिया (5)

नौर

न्यूकोलोडोनिया

न्यूजेंडिसेस (प्रि और क्र०)

हियू

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुआ न्यू गिनी

सोलोमन द्वीप समूह (प्रि)

टोंगा

वालिस और फनुना

परिचमी समान्द्रो

9. यूरोप :

साइप्रेस

जिब्राल्टर

ग्रीक

माल्टा

स्पेन

तुर्की

युगोस्लाविया

(क-2) श्रो० पी० ई० सी० के सबस्थ या सहयोगी देश :

अर्जेन्टीना

बोनिविया

लीबियाई अरब गणतंत्र

गेवान

नाइजीरिया

इंडिया

बेन्जुएला

ईरान

ईराक

कुवैत

कातार

सउदी अरब

प्रादृष्टानी

इच्छोनेशिया

(1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुआ औमिनिका, प्रेनेडा, सेंट किट्स (सेंट फिल्मोर्फी) नेविन अगुइला, सेटलुमिया और सेंट विमेन्ट ।

(2) मुख्य द्वीप : मोलेसरल, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह ।

(3) अजमान, खूबल, फजाइरैह, रास अल खैमाह शारजाह और उम अलं क्वैदेन ।

(4) अबन और विभिन्न मुलतत्त और अमीरत सहित ।

(5) सोसयटी द्वीपसमूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह ट्रोमोंट, जापिंग्यर यु, और माकेन द्वीप समूह

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का द्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

अनुबंध-2

पात्र पर्याप्त सूची

1. रोल्ज़ ।
2. विशेष इस्पात और मिथधातु इस्पात महित इस्पात ।
3. ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनियोग के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे ।
4. रसायन ।
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उत्थान के लिए फालतु पुर्जे, संघटक और कच्चा माल ।
6. विज्ञानी के हस्तों के लिए संघटक, संयोजक और फालतु पुर्जे ।
7. मणीसरी, संकटक, संयोजन, फालतु पुर्जे और कच्चा माल ।
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उत्थोग निगम के लिए मणीसरी और उपस्कर ।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग परियोजना के लिए मणीसरी और उपस्कर ।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मर्दे जिनपर आपस में सहमति हो ।

अनुबंध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र
सं०

सेवा में, दिनांक
सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
भारतीय कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय: 1980-81 के लिए 2.46 विलियन जापानी अनुदान सहायता में
के अधीन जापान से प्राप्ति ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से
जो कि आयात के संबंध में है सम्बद्ध संभरक के नाम
के माम से बैंक अक इडिया, टोकियो के लिए प्राधिकार-
पत्र जारी करने के लिए हम आपको तिम्मनिहित व्यारे प्रस्तुत करते
करते हैं :-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह
तारीख जिस जिस तक वैध है ।
- (ग) प्राप्ति के तरीके-कथा यह भीधे त्रय या औपचारिक रूपे
अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए
कि क्या संविदा का नियंत्रण उपयुक्त भूततम तकनीकी प्रस्ताव
के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लगत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रूपये में भुगतान की
जाने वाली भारतीय एंजेंट के कमीशन की भवनराशि

- (ज) वह कुल लगत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान
के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।
- (झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक ।
- (झ) संभरक का नाम और पता ।
- (ट) वे भुगतान गर्ते और संभावित तिथि जिनकों संविदा के प्रत्यर्गत
भुगतान देय होंगे ।
- (ठ) सुपुर्बंगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
- (ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय विए जाने वाले
दस्तावेज । प्रत्येक सेट की संख्या और तिथिन का सकेत करें ।
प्रत्येक सेटों की सं० और उनका निपटान दिखाते हुए ।
- (ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-प्रिपरेंट को अनुमति दी
गई है या नहीं निविष्ट कीजिए) ।
- (त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उसी लाइसेंस के धर्तीत संविदा (संविदाओं) कर दी
गई है । यदि हां, तो ऐसी संविदा की विवाक और मूल्य ।

भवदीय ।

अनुबंध-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई विल्नी, दिनांक :

सेवा में,

बैंक प्राफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय: 2.46 विलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन प्राप्ति
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

1. प्राप्तके बैंक के साथ 13.3.79 को किए गए समझौते की शर्तों
के अनुसार आपको इतव्यार्था यथा संकेत व्यारे (जो परिशिष्ट में दर्शाए
गए है) के अनुसार संविदा के नाम
में येन धनराशि के भुगतान के लिए
प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावरी के बारे
में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति
जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इच्छ
मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान
परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. प्रायातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आविष्कार के लिए भाइंगे
साहृदय प्रदान किए जाने वाले बैंकिंग भाइंगे टोकिया में भारतीय दूतावास
आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रदान किए गए लदान दस्तावेज के आधार
पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित
प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन आगे नहीं किया जासकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र संलग्न विनाक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाना है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया टोकियो ब्रांच में वस्तवजे प्राप्त करने पर विवेशी संभरकों को यैन / यूएम० आलर / पॉड के बराबर रूपया जमा करने की अवस्था करें। विवेशी संभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर रूपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० ४८-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७६ दिनांक १७-१-७६ या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय पर जारी की जाए, के अनुमार विवेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रतिलिपि परिवर्तन की मिथित वर पर की जाएगी। विवेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० ४६-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७६ दिनांक १६-६-७६ के प्रति सार पहले ३० दिनों के लिए ९ प्रतिशत वार्षिक दर पर अप्रीर इम्प्रेस्ट्रिक की गणना की गई अवधि के लिए १५ प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा प्रथम् वह तिथि जिसको विवेशी संभरक को भुगतान किया जाना है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रूपया निषेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुल्य उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिखित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात वस्तवजे जो का मूल सेट विए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई लिली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीम हजारी, लिली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाक्षा या इसकी अनुसंधान संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया तीम हजारी शाक्षा, लिली-६ (आदेशित और आवाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुन्ही के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में प्राप्तका आयात सार्वजनिक सूचना सं० २३३-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ६८, दिनांक २४-१०-६८, सं० १३२-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७१, दिनांक ५-१०-७१, सं० ७४-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७४, दिनांक ३१-५-७४ और सं० १०३-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७६, दिनांक १२-१०-७६ की गणनी की ओर विनाया जाना है। लेखा शीर्ष विभाग में धनराशि जमा की जाएगी वह “के रिपोजिट्स एंड एडवासिंज-४४३ सिविल हिपोजिट्स—हिपोजिट्स कार परवेजिस एटसेक्ट्रा एक्राह-परवेजिस प्रांट एह फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार १९८०-८१ (ये २.४६ विलियन प्रांट एह लेवट रिलीफ)।”

जिन मामलों में तुल्य रूपया दियर्वं बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीम हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० १३२-आई० टी० सी० (पी० एन०) / ७१, दिनांक ५-१०-१९७१ के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाक्षा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अत्रोपनत सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :— सहायता लेखा तथा लेखा परेशान नियंत्रक, विन मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू० सी० थो० बैंक विनिंग संसद भाग, नई लिली।

जिन मामलों में तुल्य रूपया उत्तर राजेन्ट मार्वेनिन मूचना दिनांक २४-१०-६८ में यथा उत्तिलिपि दर्शनी हुन्ही द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। मध्य मामलों में व्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए सुल्य रूपए का पूरा द्वारा इन विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों महित यदि कोई हो तो, बैंकियां खर्चे आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इंडियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाक्षा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय लाइसेंस, टोकियो

5. प्रबर सचिव (टी०ए०) शाक्षा, विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

परिशिष्ट-२

जापान के सरकार द्वारा प्रदान किए गए १९८०-८१ के लिए २.४६ विलियन के आपानी अनुदान महायना आर०ई०पी०इ० और विकासशील देशों के लक्ष में संगठित की गई है। अनुदान, इस अर्ण के अधीन धर्मिप्राप्त की जाने वाली पृष्ठ वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-१ की मूली में उद्धृत अनुसंधान देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इसे अर्ण के अन्तर्गत पात्र सांत देश होंगे। इस अनुदान महायना के अधीन जो पात्र मद्दें आयात की जा सकती हैं उनकी मूली अनुबन्ध-२ में दी गई है।

(१) जापान के सरकार द्वारा प्रदान की गई २.४६ विलियन जापानी अनुदान महायना आर०ई०पी०इ० और विकासशील देशों के लक्ष में संगठित की गई है। अनुदान, इस अर्ण के अधीन धर्मिप्राप्त की जाने वाली पृष्ठ वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-१ की मूली में उद्धृत अनुसंधान देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इसे अर्ण के अन्तर्गत पात्र सांत देश होंगे। इस अनुदान महायना के अधीन जो पात्र मद्दें आयात की जा सकती हैं उनकी मूली अनुबन्ध-२ में दी गई है।

(२) लाइसेंस पर एक शीर्षक “१९८०-८१ के लिए २.४६ विलियन जापानी अनुदान महायना” होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस सकेत “एमजे०एन०” होगा। ये प्रत्यय मुक्त नियंत्रक, आयात-नियंत्रित के आयात लाइसेंस के प्रभ्रेपित पत्र में दुख्याएं जाएंगे।

(३) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण भारतीय बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अन्तरिक्ष विवेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी अनुदान अधिकर्ता को आरंतीय रूपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे अनुदान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभ्रातिन किए जाएंगे।

(४) आयात लाइसेंस नागन-वीमा-भास्त्रा के आधार पर १२ महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधाना में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुदान) से परामर्श करेगा।

(५) पक्षे आवेदण अनुबन्ध-१ में उत्तिलिपि उ.प.न.या अन्य पात्र देशों में वित्त विवेशी संभरकों को लाभ-वीमा-भास्त्रा या सागत सथा भास्त्रा के आधार पर या नागत और भास्त्रा के आधार पर विए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की वित्ति से ४ महीनों की अवधि के भीतर (प्रबर सचिव) आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुदान) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। “पक्षे आदेशों” का अर्थ विवेशी संभरकों को आरंतीय लाइसेंसधारी द्वारा विए गए उन कार्य आदेशों या कार्य संविवादों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त

आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्पित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकारियों के आदेश शीर्या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

(16) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुबालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा (5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं विए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिये जा सके इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देंगा चाहिए। आदेश देने की अवधि में दृढ़ि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पाकाना के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए दृढ़ि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि दृढ़ि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए भारी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपद्धर रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग), नार्थ अलाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी दृढ़ि के लिए प्रत्येक मामले को पाकान के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोल लावान के लिए आविधी तिथि मिश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1982 के बाद की न हो।

खंड-2 संभरण ठेके का समझौता करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—

(21) (क) ठेके का लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा मूल्य येन भा य००एस० इलर या पौंड स्ट्रिंग में एक बेन, एक सेंट या एक बेन से कम की भिन्न के बिना ही अधिवक्त द्वारा चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारी का कामीशन, आदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अधिवक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यात निःशुल्क लागत बीमा औह भाड़ा घनराणि प्रलग प्रदायित की जा सकती है। परन्तु ठेके में आल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का अच्छा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराणि होगी।

(ब्र) संविदा में नक्त आधार पर अर्थात् बैक ग्राफ इडिया, टोकियो की जापानी संभरकों द्वारा पोतवान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की अवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रम-आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल भेजेंगे में होने चाहिए।

(22) आयात लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक संविदा की जाती चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रतिष्ठित की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के नकाल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

(23) संभरक की पाकाना :

संभरक पाल्स लोट बेशों का राष्ट्रिक होगा या पाल्स लोट बेशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खंड-3 संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए:—

(1) 1980-81 के लिए 2.46 विलियन के अनुबालन सदायर्थता से संबद्ध इस संविदा की अवस्था 18 मार्च, 1981 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुमार की गई है।

(2) संभरकों को भुगतान उगा “भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र” (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1980-81 के लिए जापानी अनुबालन सहायता के अधीन बैक ग्राफ इडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेक्सा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, य००३० औ० बैक विलिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अनुमति हो।

(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की अवस्था करने की तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुरक्षी के कार्यक्रम को भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अधेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियो को अधिसूचित कराएगा जिससे उचित अवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आणविक अवौद्धि देने हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन:—

(1) जैसे ही आदेशों को प्रतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विवित हस्ताक्षरित ठेकों की चार प्रतियां या समुद्रपार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रम आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां के साथ अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में “ए/पी” जारी करने के आदेशों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां और इसके साथ भारतीय स्टाम्प अधिवक्तियम की धारा-31 के अधीन स्टाम्प भायुक्त द्वारा विधिवत् न्यायिनीत अनुबन्ध-5 में निर्धारित प्रपत्र में बैक गारन्टी भी अवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ अलाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

(2) बैक गारन्टी कितनी धनराणि के लिए भेजी जानी चाहिए :

बैक गारन्टी उस विदेशी मुद्रा की धनराणि के रामतुल्य रुपए के लिए होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार की मार्ग की गई है और अनुबन्ध-5 में दर्शाए गए अवाज और अन्य खर्चों भी इसमें शामिल होने चाहिए। परिवर्तन की दर राजस्व द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर होनी जो कि मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियांत्र द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 की कठिका-2 के अनुसार आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को लागू होती है। इस दर का अभियांत्र: केवल लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की गई बैक गारन्टी के मूल्य से है। आयात की कीमत शुरूने के लिए सरकारी लेखे में रुपया जमा करने के लिए समतुल्य रुपए का नीचे खंड-5 में दर्शाए गई विधि के अनुसार दृसाव लगाया जाएगा।

(3) यदि ठेके के दस्तावेज “ए/पी” जारी करने के लिए बैक गारन्टी और अन्य संबंधित दस्तावेज सभी पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (जापान अनुभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेक्ता एवं लेक्ता

परीक्षा नियंत्रक, विन मंत्रालय यू०मी०ओ० बैंक विनियुग, भ्रमानी मणिन, पालियामेंट स्टॉट, नई दिल्ली और भारत के राजदूतावाय, टोकियो का भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(4) उपर्युक्त खंड 4(3) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सभावया लेखा एवं लेखा परंपरा नियंत्रक, आर्थिक वार्ष विवाह, विन मंत्रालय, पालियामेंट स्टॉट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया टोकियो के लिए अनुबंध-1 के रूप में जापानी संभरकों को “भ्रमानी भ्रमने के लिए भ्रमानी व्यवस्था (ए/वी)“ जारी करेगी। ए/वी की प्रतियां भारत के राजदूतावाय, टोकियो, प्राप्तावाय, भारत में आयातक के बैंक प्रौद्योगिक जापान अनुभाव, आर्थिक कार्य विवाह, विन मंत्रालय को पुस्ताकित की जाएंगी।

4(5) भ्रमानी के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो, जापान की सरकार, भारत के राजदूतावाय टोकियो भारत में बैंक के आयातक प्रौद्योगिक भ्रमानी लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए हम प्राप्ति की सूचना में संभरक को अवगत घराएंगा।

4(6) पोतलदान प्रधार्की करने के बाद विवेशी संभरक अपने थैकरों के माध्यम से ए/वी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। अब दस्तावेज महीन पांच बार एवं बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विवेशी संभरक को उनके थैकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(7) संभरक के लिए ए/वी जारी करने के लिए और भ्रमानी की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देव बैंक व्यवस्था भारत में आयातक के संबंध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली में भारत मंत्रालय के लेखे प्रभावित किया जाएंगे।

खंड 5—स्पृथा भ्रमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनियम पांच परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो, द्वारा भारत में आयातक के संबंध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय रेटेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध 3 के न में उल्लिखित है) की शास्त्रा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम में दस्तावेज का सुनिश्चय कर नेने के बाद ही संबंध आयातक को देने चाहिए कि विवेशी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बगाबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के संबंध सहित संभरक को भ्रमानी कर दिया गया है और उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भ्रमानी की लियि से वास्तविक रुपया जमा करने की लियि नकहीं की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिये 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पी/एन)/76, विनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। व्याज दोमों दिनों, अवधि जिस दिन विवेशी संभरक को भ्रमानी कर दिया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। विवेशी सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पी/एन)/76, विनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पी/एन)/74, विनांक 31-5-74 भ्रमानी की येन धनराशि के बगाबर रुपया की गणना करने के लिए प्रपनाई जाने वाली विनियम वर मुख्य नियमक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पी/एन)/76, विनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियमक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियमण परिवर्तन के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायगा। इस बात की सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबंध सारतीय बैंक का होगा जिस आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारों लेखे में

गहरे रूप से जमा कर दी गई है। सार्वजनिक बैंकों की भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि विवेशी संभरकों में दस्तावेज जेने में प्रदर्शन हो रहे धनराशि लेखे में मध्ये रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त संपादन जमा करना चाहिए वह “के डिपोजिट पृष्ठ प्रश्नामिल-843 सिलिंग डिपोजिटम—डिपोजिटम फोर पर्चेजिंग पट्ट परचेज लक्सदा एंड परचेजिंग/पट्ट पृष्ठ काम गवर्नरमेंट आपान पार 1980-81 (पैन 2,46 विविध नांगों पार 1980-81 क्रम गवायना)।

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नीम हजारी, दिल्ली में सरकारी भी साथ में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुनिश्चित न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शास्त्रा या इसके उपर्युक्त किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (दुष्कीर्ती) में प्राप्त एक दृष्टि (डिपोजिट ड्राफ्ट) के साथम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, नीम हजारी शास्त्रा, विनांक 6 (दृष्टि याहक और प्राप्तक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पी/एन)/68, विनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पी/एन)/68, विनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी (पी/एन)/71, विनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पी/एन)/74, विनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पी/एन)/76, विनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए क्षम प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबंध भागीदार बैंक भी ऊपर निर्धारित सरीके से वह अतिरिक्त धनराशि मेवा लेखों के नियम भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालावों को भरने संबंध आयातकों/उनके थैकरों को इस बात का सुनिश्चय कर नेना चाहिए कि भारतीयकृत सूचना सं० 103-आईटीसी (पी/एन)/76 विनांक 12-10-76 के साथ पही जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132 आईटीसी (पी/एन)/71 विनांक 5-10-71 के पैग 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74 आईटीसी (पी/एन)/74 विनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना वालान के कालाम “धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण स्वीरे” में निरपवाद रूप से निरिष्ट किए गये हैं। वालान वालान में निम्न-लिखित व्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) विस मंत्रालय के भ्रमानी के लिए प्राधिकार पत्र सं० भौर विनांक
- (ख) वेन मुद्रा की बह धनराशि जिसके संबंध में प्रपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ लिखेप किए जाने हैं।
- (ग) विवेशी संभरक को भ्रमानी करने की लियि
- (घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि
- (इ) (व्याज की गणना जापानी संभरक की भ्रमानी की लियि से सरकारी लेखे में समस्त स्पृथा जमा करने की लियि तक की अवधि के लिए की जानी है।

उनके प्रभावात् सी० १० ए० ए० ए० ए० द्वारा जारी किए गए भ्रमानी के लिए प्राधिकारपत्र का संबंध देने हुए और भीजक तथा पीत परिवहन दस्तावेजों को संस्थान करने हुए वालान लेखा जमा करने का साथ देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० १० ए० ए० ए० ए० ए० को भेजा जाना चाहिए।

ट्रिप्पणी: भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निषेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से व्यावायी भी सूचना और अप्रतिकृतीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तालाक भाव सी० १० ए० ए० ए० ए० ए० ए० विस मंत्रालय (प्राधिकारी कार्य विभाग) नई विनांक को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबंध बैंक आफ इंडिया की लाइसेंस की सूचना विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निषेपों की धनराशि का पूँजीकृत करना चाहिए और अपेक्षित “एम” प्रति पर धनराशि रिजर्व बैंक आफ इंडिया बैंकी की भेजना चाहिए।

5(8) वित्त मंत्रालय के सी०ए०ए०ए० ए० द्वारा आरी०ग्र०ग्र० ई० गारंटी और प्राधिकरण के मामले में उत्तरदायित्व पूरा करने के बाद भारत में संबद्ध ई० सी० ए० ए० ए० को वैक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रयोगत के लिए अनुबंध 6 में निर्दिष्ट प्राप्त में आवेदनपत्र भेजें।

बाण्ड 6 विविध शर्तें :

6(1) आधार नायंसेस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के प्राधिकारपत्र जारी होने के बाद आधारक को पीतमवालों और उसके प्रधीन किए भुगतानों के संबंध में और जो बोतलवान होने वाले हैं, उसके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी० ए० ए० ए० ए० प्रार्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय वैक ग्र०ग्र० ई० विलिंग, संबंध मार्ग नई विल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आधार लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक की अवगत करारें जो समझते था पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3) विवाद :

यह समझ लेता चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। वैक दाक ई०ग्र०, टोकिबो द्वारा भुगतानों से पूर्ण संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साक्षात् “भुगतान के नियम” के प्रधीन अनुबंध 1 में वर्णाई जानी चाहिए। विवारों से निवटने की शर्तें डेके थी शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) परिष्य अनुदेश :

आधार लाइसेंस या उसके संबंध में उठ जाए होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1980-81 के लिए अनुदान तहायता के प्रधीन सभी आधारों की पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों या अनुदेशों या आवेदों का लाइसेंसधारी की तुरन्त पालन करना हीगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त शब्दों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आधार-नियांत (नियंत्रण) अधिनियम के प्रधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6) अनुबंधों की सूची :

अनुबंध-1 पात्र लोत देशों की सूची

अनुबंध-2 पात्र पर्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध-3 भुगतान के लिए प्राधिकार पर जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध-4 भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र (ए/पी) का प्रपत्र

अनुबंध-5 वैक गारंटी का प्रपत्र

अनुबंध-6 वैक गारंटी रिहा करने के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र

अनुबंध 1

पात्र लोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उसके देश :

(क-1) मान-वी० वी० ई० सी० विकासशील देश :

1. अफ़्रीका उत्तरी तहान :

मिस्र

मोरीक्को

तुनीशिया

2. अफ़्रीका, दक्षिणी तहान :

अंगोला

बोस्फ़ाना

बर्न्दी

कोमोर

केप बर्डी ई० समूह

केन्ट्रीय अफ़्रीका गणराज्य

चाद

कमोरो ई० समूह

इथोपिया

जामिया

जांगो, बोमोह गणराज्य

इक्वेटोरियल गांडीना

याना

गिनी

माइक्रो फोस्ट

कीनिया

लेसोथो

लाइबेरिया

मालायासी गणराज्य

मलावी

माली

मारिलिया

मारीशिया

मोजाम्बिक

नाइजीरा

पुर्तगाल गिनी

[रियुनियम

रोडेनिया

रवान्दा

सेस्ट्रैलिना और डेप (2)

साप्पोटोम ग्रिनान्ड

सेनेगल

लेबिलिस

लियरा लिबोन

लीमालिया

सूडान

स्वाजीलैंड

टेरों अफ़्रीस और इस्मास

टोगों

दुगान्डा

तन्जानिया गणराज्य संघ

अपर बोल्डा

जाम्बोरे गणराज्य

जामिया

3. अमेरिका उत्तरी भौत केन्द्रीय :

बेहसम
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टोरिका
कूरा
डोमिनिकन गणराज्य
एल साल्वादोर
गुटाडेलोप
खाटेमाला
हेटी
होल्डूरम
जेमेका
मार्टिनिक-कूरा
मेक्सिको
भीवरलैंड एकाडिलीज
विकारगुप्ता
पत्तामा
सेट पियरी भौत विकूलोम
ट्रिनिडाद भौत टोडोगो

बेस्ट इन्डीज (शास्त्रा) एन-पार्स-हॉ

(क) संबंधित राज्य (1) |
(ख) आंतरिक राज्य (2)

4. दक्षिणी अमरीका :

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फालकलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गूयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बहून
इजराइल
जोर्डन
नेबनान

1. पहले स्तरीय गिरी का प्रदेश, पपमेडी पी द्वीप समूह

2. निम्नलिखित द्वितीय भौतिक : असेमन, द्रिस्टन आ इत एवं संसिविलिस, नाईटिगेन गफ

3. मुंबई द्वीप समूह, अस्था बोनाहरे क्युराकाओं, साहा, सेन्ट युस्टालिट सेन्ट मारटिन (वर्षिण भाग)

ओमन

सिरिपाई भरव गणराज्य
यूनाइटेड भरव गणराज्य
यमन भरव गणराज्य (3)
यमन जनवादी डी. आर. (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालद्वीप
नेपाल

7. दक्षिण पूर्वी एशिया

बुर्मे
हांगकांग
बांगलेर गणराज्य
कोरिया गणराज्य
लाओस
मकांगो !
मलेशिया
फिलिपीन

सिंगापुर
ताइवान
याइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणराज्य
वियतनाम जनवादी गणराज्य

8. ओसिनिया :

फोको द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट भौत इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पीसिनेशिया (5)
गीह
न्यूकोलेडोनिया
न्यूहोसिसेस (प्रिमोर फ)

हियू
वैसिपिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलाग्न द्वीप समूह (प्रि)
टोगो
वानिस भौत फ्लुना
पश्चिमी समान्त्रो

9. यूरोप :

जाइमेस
जिफाल्टर
प्रीक

माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप: ग्रेटिंग्स्ट्रा, डोमिनिका, मेसेला, सेट डिट्स (सेट निस्टोफी) बैंकिल अग्निला सेट मूलिया और मेंट विलेन्ट।
- (2) मुख्य द्वीप: मौनेसारन, मेमान, नुक और काक्कोम, और त्रिटिश वरिजन द्वीप समूह।
- (3) अजमलन, द्वाल, कजाहरह, रास अल खेमाह नारजाह और उम अल खेवन।
- (4) अवन और विभिन्न मुलानन और अमीरन सहित
- (5) सोसायटी द्वीप समूह ताहिसी भूमि को शामिल करते हैं अस्ट्रेलिया द्वीप समूह ट्रोमोट, जामियर औप आर माकेसन द्वीप समूह।
- (6) नेपिलिक द्वीप समूह का दृष्ट प्रबंध: कारोलीन द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) रो० पी० ई० सी० के सदस्य या मह्योगी वेश:

अल्जीरिया

ओस्त्रिया

सीवियाई अरब गणतन्त्र

वेनान

नाइजीरिया

इस्लेमोर

बेन्युएल

इरान

इराक

कुवैत

कातार

सऊदी अरब

आबुधाबी

इण्डोनेशिया

अनुबन्ध 2

पात्र पृथ्ये तूर्ची

1. रोस्त्र
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात महिन इस्पात
3. ट्रूकों और ट्रैक्टरों के विनियोग के लिए संबंधक, संयोजक और पुर्जे
4. रसायन
5. जातान अनुवान परियोजना और भारत-जापान खेलस्ट्रेट उद्यम के लिए कालामु पुर्जे, संबंधक और कम्पना माल
6. विजली के हल्लों के लिए संबंधक, संयोजक और कालामु पुर्जे
7. मशीनरी, संबंधक, संयोजक, कालामु पुर्जे और कम्पना माल
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग के नियम के लिए मशीनरी और उपकर
9. तेज एवं प्राइविक गैस आयोग परियोजना के लिए मशीनरी और उपकर
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मद्दें जिन पर आपस में सहमति थीं।

अनुबन्ध 3

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रारंभ-पत्र

मयन—

दिनांक

मेवा में,

गहायना लेखा नथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक,
वित्त मकालय,
आधिक कार्य विभाग,
गृ० सी० श०० बैंक विलिंग, प्रथम मंजिल
पार्लियांसेट स्ट्रीट,
नई ट्रिली-110001

विषय—1980-81 के लिए 2.46 विलियन जापानी अनुवान महायना येन के अधीन जाता है।

महायन,

उपर उल्लिखित अनुदान महायना के अधीन जापान से जोकि आयात के संबंध में है, सम्बद्ध संभरक के नाम में बैंक ब्रॉक इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित व्योरे प्रस्तुत करते हैं:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) प्रायात लाइसेंस की संख्या, विनांक और मूल्य और वह वारीय जिम तक बैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—यह साधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके भासले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का नियम उपयुक्त त्यन्तम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रूपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एंजेंट के कमीशन की धनराशि
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और विनांक
- (झ) संभरक का नाम और पता
- (झ) वे भुगतान शर्तें और सभावित नियम जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगी।
- (ঠ) शुरुदर्दी को पूर्ण करने की प्रत्याशित नियम
- (ড) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय दिए जाने वाले वस्ताविज (प्रत्येक सेट की संख्या और नियटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका नियटान विज्ञात हो।
- (ঢ) पोनलदान अनुदेश (वाहनान्वरण/पार्टिशनमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं तिप्पिणी कीजिए।
- (ণ) भारत में प्रायातकों के नाम और पता
- (ত) बैंक-गमरस्टी(यू.) की संख्या, विनांक और मूल्य और वैध करने के बैध है, को भी व्यापार्या जाए।
- (থ) यह उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है, यदि तो, मोंगोली संविदा की विनांक और मूल्य।

भवद्वय,

अनुबन्ध 4

मंत्र्या

भारत भरकार

वित्त मन्त्रालय

आधिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

संवाद में,

बैंक आॅफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय—2 46 विनियन के लिए जापानी अनुवान गहायता के अधीन आयान भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रेय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एनव्हारा यथा संलग्न स्वरूप (जो परिशिष्ट में दिये गए हैं) के अनुसार संबंधी के नाम में ये धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. हृष्या भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पात्रता के बारे में सभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान मंत्रालय, आयातक बैंक, भारत के गोदावासम, टोकियो और इम मन्त्रालय को पृष्ठाकृत की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा समझौते लाना दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाँड़े महिने अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाईटे टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लादान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संतोलय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस संतोलय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र तक बैंध रहेगा।

भवतीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित का विवित—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनमें निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आॅफ इंडिया, टोकियो, ब्रॉन्च से दस्तावेज प्राप्त करने पर विवेशी सभरकों को येन/पू०एस०डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विवेशी सभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विवेशी सभरकों को भुगतान करने की नियम की यथा प्रत्यक्षित परिवर्तन की सिद्धि दर पर की जाएगी।

विवेशी सभरक को भुगतान करने की नियम से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की नियम सकं भी अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 16 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत आधिक दर पर और इसमें अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर पर सेव्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। व्याज दोनों तिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह नियम जिसको विवेशी सभरक को भुगतान किया जाता है और वह नियम भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निशेष किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को भीमा एन्क्रूप निकासी के लिए आयान दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व गहर धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या सो रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, शीम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। या स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुपस्थित संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, शीम हजारी शाखा, दिल्ली-6 (सार्वजनिक और आश्राम) के नाम से और गकों देव वर्षानी दुर्घटी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 233 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा भीषण जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के लिए जिटम एड ग्रांड्रामिज-843 मिलियन डिपाजिट-डिपांजदेस फार परवेजिम एटेक्ट्रा एक्स्प्रेस एड्रेस-एन्ड-जिम्मेदार फार दि गर्वेंटेंट आॅफ जापान फार 1980-81 (ये 2.46 विनियन घास्ट एड डेनट रिलीफ)।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, शीम हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आॅफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना दिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेण-पत्र माहूत उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा नदा लेखा परीका नियक्तक,
वित्त मन्त्रालय (आधिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक इलिंडा,
संयद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिस मामले में तुल्य रुपया अपर भकेनित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुए ही द्वारा प्रेषित करना है उसकी रुचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ड्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके बारे जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा व्युत्तर इस विभाग को भेजना चाहिए।

समूद्र पार सभरक के बैंकर के खर्च सहित यदि कोई हो सो, बैंकिंग खर्च और बैंक आॅफ इंडिया, टोकियो ब्रॉन्च के अन्य अर्थ इण्डियन बैंक आॅफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही नियरित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर मंजिल (टी ए) शाखा, वित्त मन्त्रालय, आधिक कार्य विभाग, मार्ग दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुच्छेद-5

[सदरमें खण्ड 4—पैग 4(2)]

गारंटी बाणज

सेवा में,

भारत के गवर्नर,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया) 2. 46 विनियन येन की जापान अनुबान सहायता की शर्तों के अनुसार संध्या ऊपर उल्लिखित कागज के मद्दे आयातक के नाम से प्राप्तान के अनुसरण में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस संध्या का पालन करने हुए के द्वारा बाद में इसे "आयातक" कहा गया है (के आयात के लिए भूगतान के लिए राजी होने हुए विदेशी मुद्रा में उपयुक्त धनराशि का संकेत करें) आयात के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत (टोकियो में वाणिज्यिक बैंक का नाम) बैंक द्वारा भूगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की तात्पूर परिवर्तित वर पर जो इन संबन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकलित किया जाता है और इसके साथ 1 प्रतिशत की विदेशी संभरक को किए भूगतान की तारीख को सरकारी लेख में क्रेडिट के लिए समतुल्य रूपए के भूगतान की तारीख तक प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक वर से और इससे अधिक की अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज के साथ भूगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के दम दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उनके क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं। जापान टोकियो में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परकार्य में उपयोग को भूगतान करने की तिथि से इस पर प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो रूपए से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भूगतान करने में देर होनी तो उसकी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भूगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी और से और सरकार की भूगतान किए जाने योग्य राशि के संबन्ध में जो राशि हमारे बैंक द्वारा दी जाती है, उस संबन्ध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर अनुसरण करने की अनिवार्य होगा।

3. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में बढ़ि होने से या प्रध्युरे माल इड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन तुश्चा है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बोड की धनराशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ निहित है, वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने सक पूरी प्रक्रिया और प्रभाव के साथ लागू होंगी और उसे तब तक

कार्यान्वयित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्ण रूपेण तुकड़ा न कर दिया गया हो और उसकी भागें पूरी त हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि बैंक के संविदान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए जिन आयातक और दि बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय के लिए अन्यथा करें और उपर्युक्त मामले के सन्दर्भ में या किसी कारणक्षण थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो लिया गया, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह आपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से वीं गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या कोई मामला या आत, चाहे जो भी हो, जो जिम्मेदारी के लिए ऊपर किया उन्मुक्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. अल में हम बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए जिना, मुद्रा माल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करें।

7. इस बोड/गारंटी के अन्तर्गत (इसमें व्याज तथा सभी बैंक खर्च भी शामिल हैं, इस गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, और यह दिन मास तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर अपार्ट 19 तक जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप से इस गारंटी के अन्तर्गत मार्गे पूरी नहीं कर दी जाती इसे लागू रखा जाएगा और जब तक ** उपरे लाद दूसरे छः मास के भीतर अपार्ट तक उनकी मार्गों के लिए मुकुटमा या कार्यालय लागू न हो जाए, इस बोड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार सभी प्रधिकारों से विवित हो जाएगी और हम लोग इसके अन्तर्गत निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिया जाएंगे।

दिन का दिनांक वास्ते (बैंक लिंग) श्री के द्वारा नाम और प्रोहवा (भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ल्यौक्षण्य)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

**यह सारीख और एक मास के साथ पद की वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी।

टिप्पणी— (1) स्वाप्न पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वयित होने वाली है, इसके मूल्य का भारतीय स्टाम्प प्रविनियम की धारा-31 के अनुसार कलनटर के द्वारा द्याज निर्णित किया जाना है।

अनुच्छेद-6

[खण्ड 5 पैग 5(5)]

बैंक गारंटी मुक्त कराने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परोक्षा नियंत्रक,

चिल मंत्रालय,

आयिक कार्य विभाग

पूनाइटिंग कमिशनर बैंक बिलिंग,

पालियामेट स्ट्रीट,

नई दिल्ली-110001

महोदय,

मन बैंक गारन्टी संक्षया विनांक
धनराशि रुपए ने अधीन
अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में इमारं द्वारा जमा किए गए रुपए की
विस्तृत जानकारी इस आवेदन के माध्य नींवे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह
बैंक गारन्टी मुक्त की जाए और इसे लौटा दी जाएः—

1. आयातक/नाइसेंसधारी जिसकी ओर से गारन्टी प्रस्तुत की गई
थी, का नाम और पूरा पता ।

2. आयात याइमें संक्षया, विनांक मूल्य और उसके अधीन आयात
के निए प्रत्युति उपस्कर और/या पर्यवर्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. सार्वजनिक खोलने के लिए विस मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण (गों) के नाम:—

(क) पत्र संक्षया और विनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) 2.46 लिंगियन येन की जापान प्रतुदान महायता

4. आयातों और जमा किए गए रुपए के स्वीके (प्रत्येक प्राधिकरण
के लिए अलग-अलग विए जाने हैं)

(क) येन/पू.एम.डॉलर/पौण्ड में बीजक की धनराशि (वास्तविक)

(ख) जमा किए गए रुपए की धनराशि

(ग) संबंधित चालान संख्या और तारीख और राजकोष/बैंक का
नाम

(घ) यदि डिमांड इफट द्वारा है तो डिमांड इफट की संक्षया और
विनांक और जिसके साथ डिमांड इफट स्टेट बैंक आफ इंडिया,
विलें को मेंजा गया था उभयों संख्या और विनांक

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और उपयोग न की गई^ग
गेय धनराशि (येन/पू.एम.डॉलर/पौण्ड)

2. हम प्रमाणित करते हैं कि:—

(1) *विस मंत्रालय द्वारा विए गए प्राधिकरण (गों) में उपलब्ध
(येन) की ऐसे धनराशि उपयोग नहीं की गई है/उपयोग
नहीं की जाएँगी ।

(2) विषयक बैंक गारन्टी के अधीन हमारे उत्तरदायित्व विश्वित
पूरे हो गए हैं ।

(3) हम पुष्ट करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो का व्याप
और बैंक के बच्चे और हम नेन देन से संबंधित सम्बन्ध
संभरकों बैंकों के बच्चे यदि कोई हो, बैंक आफ इंडिया,
टोकियो को इसमें भूगतान कर दिए हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारन्टी रुपया मुक्त कर दी जाए
और इस करने के लिए इसे लौटा दी जाए ।

भवदीय

(बैंक की ओर से प्राधिकरण प्रेसेंट)

*जो भी लागू हो ।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/81

New Delhi, the 28th May, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing Condition pertaining to Japanese Grant
Aid of Yen 2.46 billion (Debt relief) for 1980-81.

File No. IPC/23(14)/80-81.—The terms and conditions
governing the issuance of import licences under the Japanese
Grant Aid of Yen 2.46 billion (Debt Relief) for importers
in both Private and Public Sectors as given in Appendix I
and II to this Public Notice are notified for information.

Sd/-

MISS ROMA MAJUMDAR, Chief Controller
of Imports and Exports

APPENDIX

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports
under the Japanese Grant Aid of Yen 2.46 Billion
(Y 2,463,559,000) (Debt Relief) for 1980-81 extended by
the Government of Japan.

Section I—General Conditions :

I(i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.46 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "SJN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating
a supply contract

II(i)(a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight among may be shown

separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier :

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III :

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Govt. of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an

'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for Rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US \$/Pound sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculate at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US \$/ £ Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81 (Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt—relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupees deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the Condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The Licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1980-81 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VI(vi) List of Annexures :

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities.

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara: St. Helena and dep. (2)

Egypt	Sao Tome and Principe
Morocco	Senegal
Tunisia	Seychelles
	Sierra Leone
	Somalia

II. AFRICA South of Sahara: Sudan

Angola	Terro. Afars and Issas
Botswana	Togo
Burundi	Uganda
Cameroun	Un. Rep. of Tanzania
Cape Verde Islands	Upper Volta
Central African Rep.	Zaire Republic
Chad	Zambia
Comoro Islands	
Congo, People's Republic of Dahomay	
Equatorial Guinea (1)	
Ethiopia	
Gambia	
Ghana	
Guinea	
Ivory Coast	
Kenya	
Lesotho	
Liberia	
Malagasy Republic	
Malawi	
Mali	
Mauritania, Mauritius	
Mozambique	
Niger	
Portuguese Guinea	
Reunion	
Rhodesia	
Rwanda	

III. AMERICA, North and Central :

Bahamas	
Barbados	
Belize	
Bermuda	
Costa Rica	
Cuba	
Dominican Republic	
El Salvador	
Guadeloupe	
Guatemala	
Haiti	
Honduras	
Jamaica	
Martinique	
Mexico	
Netherlands Antilles	
Nicaragua	
Panama	
St. Pierre & Miquelon	
Trinidad and Tobago	

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island and Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inacessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin (Southern part).

eligible source countries under the Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months from valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II (i) (a) The CIF or C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. If no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier—

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a judicial persons registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III—

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 and will be subject to the approval of Government of India.

III (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the format Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure V duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

IV (ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed : The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to Pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure V. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)78, dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section V below.

IV (iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section will approve the

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupees deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the Condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The Licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1980-81 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities.

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories :

(a) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara: St. Helena and dep. (2)

Egypt	Sao Tome and Principe
Morocco	Senegal
Tunisia	Seychelles
	Sierra Leone
	Somalia

II. AFRICA South of Sahara: Sudan

Angola	Terro. Afars and Issas
Botswana	Togo
Burundi	Uganda
Cameroon	Un. Rep. of Tanzania
Cape Verde Islands	Upper Volta
Central African Rep.	Zaire Republic
Chad	Zambia

Comoro Islands

Congo, People's Republic

of Dahomay

Equatorial Guinea (1)

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

Malawi

Mali

Mauritania, Mauritius

Mozambique

Niger

Portuguese Guinea

Reunion

Rhodesia

Rwanda

III. AMERICA, North and Central :

Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

Costa Rica

Cuba

Dominican Republic

El Salvador

Guadeloupe

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Martinique

Mexico

Netherlands Antilles

Nicaragua

Panama

St. Pierre & Miquelon

Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island and Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin (Southern part).

eligible source countries under the Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on he overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months from valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i) (a) The CIF or C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. If no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier—

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III—

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 and will be subject to the approval of Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalized, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the format Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure V duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

IV(ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed : The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to Pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure V. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-JTC(PN)78, dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section V below.

IV(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section will approve the

contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, 1st Floor, Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

IV(iv) On receipt of the documents mentioned in Section IV(iii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(v) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the C A A & A.

IV(vi) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vii) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payment is made to the supplier along with interest charges thereon calculating at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any

one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76, dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposits in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 and also Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 10-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalent into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for the purpose be made in the form laid down in Annexure-VI.

Section-VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must clearly

2. Importer's Banker _____ they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US\$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any Change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC-(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes records from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank, and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

ANNEXURE V

[Ref. Section IV—Para IV(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens|US Dollars and £ Sterling for the import

of _____ by _____ (hereinafter called 'importer') against the import licence No. _____ dated _____ issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we _____ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices|A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the _____ (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. _____, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We, _____ (Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of his guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the _____ (Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the _____ (Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ (Bank) from its such liability.

6. We _____ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, 1st Floor, Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

IV(iv) On receipt of the documents mentioned in Section IV(iii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(v) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the C A A & A.

IV(vi) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vii) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payment made to the supplier along with interest charges thereon calculating at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any

one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76, dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposits in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers' bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 and also Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 10-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for the purpose be made in the form laid down in Annexure-VI.

Section-VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must clearly

2. Importer's Banker _____ they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US\$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any Change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC-(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes records from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank, and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

ANNEXURE V

[Ref. Section IV—Para IV(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens|US Dollars and £ Sterling for the import

of _____ by _____ (hereinafter called 'importer') against the import licence No. _____ dated _____ issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we _____ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices|A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the _____ (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. _____, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We, _____ (Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of his guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the _____ (Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the _____ (Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ (Bank) from its such liability.

6. We _____ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and all banking charges, not exceeding 1 per cent of the guaranteed amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

→ (month) 19_____. Unless claims under this bond|guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto all Government's rights under this bond|guarantee shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____ 19
for _____ (Bank)

Accepted for and on behalf of the
President of India by Shri _____

(Name and Designation)

Signature

Signature

Note: The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE VI

[Section V—Para V(v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in the discharge of our obligations under Bank Guarantee No. _____ dated _____ for an amount of Rs._____ with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer|licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence No. date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each authorisation).

(a) Letter No. and date.

(b) Amount of Authorisation.

(c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation).

(a) Amount of Invoice (net) in Yen|US\$|£.

(b) Amount of Rupee deposit.

(c) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(d) If by demand draft, No. and date of the demand draft and No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (Yen|US\$|£). in each Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen_____ available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

(2) Our obligation under the Bank Guarantee in question have been fully discharged.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

